और... एक शेर

मंज़िल न दे चराग़ न दे हौसला तो दे,
तिनके का ही सही तू मगर आसरा तो दे
- राणा सहरी

लोकमत समाचार
तमसो मा ज्योतिर्गमय

आचरण रहित विचार कितने ही अच्छे क्यों न हों, उन्हें खोटे मोती की तरह समझना चाहिए. ■ महात्मा गांधी

संपादकीय

सूखे की समस्या का स्थायी निदान खोजना होगा

भारतीय मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि राज्य सहित पूरे देश से मानसून की समय से पहले विदाई होने जा रही है. महाराष्ट्र कम बारिश की वजह से अकाल की चपेट में है. सरकार ने 355 तहसीलों में से 69 में सूखे जैसी स्थिति की घोषणा की है. जहां देश भर में बारिश सामान्य से 14 प्रतिशत कम हुई है, वहीं राज्य के मराठवाड़ा में 45 प्रतिशत कम हुई है. कृषि मंत्रालय के सर्वेक्षण के मुताबिक मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र के 12 जिलों के चार हजार से ज्यादा गांव पानी की कमी से बुरी तरह से जूझ रहे हैं. राज्य के बांधों में भी पानी बीते सालों के मुकाबले बहुत कम है. राज्य में किसानों की बढ़ती आत्महत्याएं भी लगातार चिंता का विषय बनी हुई हैं. राहत की बात है कि इससे निपटने के लिए केंद्र के साथ-साथ राज्य सरकार ने भी कमर कस ली है. केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से राहत पैकेज की विस्तृत योजना मांगी है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्र के मंत्री नितिन गडकरी पूरी संवेदनशीलता के साथ इस समस्या से निपटने में लगे हैं. राज्य सरकार ने सूखा प्रभावित जिलों के किसानों के बारहवीं कक्षा तक के बच्चों की स्कूल फीस माफ करने का फैसला किया है. साथ ही इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई कर रहे विद्यार्थियों को फीस में 50 प्रतिशत की राहत देने की बात भी राज्य के राजस्व मंत्री ने की है. सूखे की मार झेल रहे किसानों की मदद के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम सराहनीय हैं. यह सही है कि इस समय किसानों की समस्या का तात्कालिक निदान निकालना जरूरी है, लेकिन इस समस्या पर वैज्ञानिक दृष्टि से समग्र चिंतन-विश्लेषण कर उसके स्थायी समाधान की दिशा में भी काम करने की बड़ी जरूरत है. अकाल का सीधा संबंध अर्थव्यवस्था से है. व्यापक शहरीकरण के बावजूद महाराष्ट्र में कृषि ही अर्थव्यवस्था का पूरक आधार है. अब राज्य को अपने संसाधन अकाल से निपटने में लगाने पड़ेंगे. बड़ा संकट यह है कि भूजल स्तर राज्य के उन हिस्सों में भी नीचे जा रहा है जहां पर्याप्त वर्षा हुई थी. राज्य में ढेरों सिंचाई परियोजनाएं कई दशकों से किसी न किसी छोटे-मोटे कारण से अधूरी पड़ी हैं. भारतीय कृषि बहुत हद तक प्राकृतिक बारिश पर निर्भर है. अगर महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति इसी तरह बनी रहती है तो आने वाले कुछ समय में देश की अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. साथ ही सूखे से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीन क्षेत्रों- आर्थिक विकास, खाद्यान्न संकट और मुद्रास्फीति पर असर पड़ना तय है. जिस तरह से सिंचाई भगवान भरोसे है और ग्लोबल वार्मिंग से बारिश का चक्र बदल रहा है उसका सीधा असर कृषि पर पड़ रहा है. दिन-प्रतिदिन हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं. ऐसे में बिना सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के सिर्फ मानसून के भरोसे नहीं रहा जा सकता. विश्व बैंक की रिपोर्ट का कहना है कि अगले कुछ सालों के बाद भारत में पानी को लेकर त्राहि-त्राहि मचने वाली है. जल संकट के कई कारणों में से एक है पानी को इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में हमारी अक्षमता. सिंचाई के कुछ तरीकों में फसलों तक पानी पहुंचने से पहले ही हवा हो जाता है. इस समस्या से निपटने के लिए कुछ रास्तों पर काम शुरू किया जा सकता है. सिंचाई के लिए फव्वारे वाली सिंचाई जिसमें कि सीधा पौधों की जड़ों में पानी की बूंदें डाली जाती हैं, अपनाई जा सकती है. एक रास्ता ऐसी फसलें बोने का भी है जो पानी पर ज्यादा निर्भर न रहती हों. सूखा, कर्ज, आत्महत्या और फिर मुआवजा- आखिर कब तक यह क्रम चलता रहेगा? सबको मिलजुलकर समस्या का स्थायी समाधान खोजना ही होगा. ■■

डुकरिया

लघुकथा

पवित्रा अग्रवाल

ससुराल से पीहर आई बेटी से वहां के हालचाल पूछते हुए मां ने पूछा, 'तेरी डुकरिया के क्या हाल हैं ?'

'कौन डुकरिया मां?

'अरे वही तेरी सास.'

'प्लीज मां, उन्हें डुकरिया मत कहो...अच्छा नहीं लगता.'

'मैं तो हमेशा ही ऐसे कहती हूं, इससे पहले तो तुझे कभी बुरा नहीं लगा...अब क्या हो गया ?'

'इस डुकरिया शब्द की चुभन का अहसास मुझे तब हुआ, जब एक बार अपनी सास को भी आपके लिए इसी शब्द का इस्तमाल करते सुना था. यद्यपि उन्होंने मेरे सामने नहीं कहा था.' बेटी ने जवाब दिया.■■

कमजोर नेता थोपने की बीमारी

आलोक मेहता
वरिष्ठ पत्रकार

घोषणाओं के ढोल कितने ही बड़े हों, आदर्शों का ओवरकोट कितना ही मोटा हो, नेतृत्व की ढाल-तलवार कितनी ही मजबूत हो - राजनीतिक दलों में असहमतियों, गुटों और अस्तित्व के संघर्ष पर नियंत्रण बहुत कठिन है. आम आदमी पार्टी के गठन और सत्ता में आने की अवधि अन्य दलों के मुकाबले बहुत कम है. दो साल में इतने झगड़े, विभाजन और विरोध के स्वर सुनाई देने पर भोले-भाले समर्थकों और मतदाताओं को आश्चर्य एवं दुःख हो रहा है लेकिन उन्हें यह याद रखना होगा कि राजनीतिक पार्टियों की यह बीमारी पुरानी है. देश में इस समय दो ही ऐसे नेता हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं और उनकी अपनी पार्टियों में उनका कोई विकल्प नहीं है. ये हैं- नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल. मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी का इतिहास पुराना है और वह आंतरिक टकराव की बीमारी झेल चुकी है. केजरीवाल नौकरशाही और जेबी संस्थाओं की 'तिकड़मबाजी' से उभरे नेता हैं. सरकारी कुर्सी और जेबी दुकान की गद्दी पर बैठकर मनमानी को चुनौती कभी नहीं मिलती. आम आदमी पार्टी के गठन और चुनावों के दौरान केजरीवाल हर बात - हर काम का फैसला सड़क-चौराहे पर किए जाने का दावा करते रहे. लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्हें राजनीतिक बिसात पर अपने प्रिय मोहरे बैठाने एवं विस्तार के लिए विश्वस्त सेवादारों की तैनाती ही जरूरी लगी. लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, भाजपा, अकाली की घमासान लड़ाई के कारण आम आदमी पार्टी के भाग्य से छींका टूट गया. इसमें कोई शक नहीं कि चुनावी मैदान में कई बार नए या निर्दलीय उम्मीदवारों को चमत्कारिक सफलता मिल जाती है. वहां पार्टी से अधिक उम्मीदवार की पहचान और

सभी पार्टियां प्रदेशों में कमजोर नेताओं को थोपने की बीमारी से ग्रस्त हैं. उनकी मनमानी को चुनौती कभी नहीं मिलती.

साख का महत्व होता है. पंजाब में यही हुआ था. केजरीवाल एंड कंपनी ने इस विजय को भी 'झाड़ू' का कमाल समझा. इस गलतफहमी के कारण कुछ ही महीनों में तीनों सांसदों के तेवर विद्रोही हो गए. दिल्ली के नवाब इसे बर्दाश्त नहीं कर पाए और दो सांसदों को निलंबित कर दिया. तीसरे सांसद भगवंत मान अपनी गायकी के लिए पंजाब में बहुत लोकप्रिय हैं. भगवंत मान और साथी सांसद धर्मवीर गांधी के बीच हुई बातचीत का ऑडियो टेप सार्वजनिक होने पर हंगामा हो गया. टेपिंग किसने की या कराई और फिर सार्वजनिक कैसे हुई, इस मुद्दे पर आरोपबाजी चली. लेकिन आम आदमी पार्टी यह नहीं कह सकी कि यह टेप फर्जी है और ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं.

असली मुद्दा प्रदेशों में कमजोर नेताओं को थोपने का है. केजरीवाल के पास सही व्यक्तियों की कमी स्वाभाविक है. लेकिन कांग्रेस या भाजपा के पास तो नए-पुराने प्रभावशाली लोगों का भंडार है. फिर भी कांग्रेस जैसी पार्टी पंजाब में करारी हार के बावजूद सही प्रादेशिक नेतृत्व नहीं दे पा रही. महीनों से प्रादेशिक नेता परस्पर विरोधी अभियान चला रहे हैं. कद्दावर नेता पूर्व मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह, पार्टी नेतृत्व की करीबी वरिष्ठ नेता अंबिका सोनी सहित कई प्रादेशिक नेता महीनों से खींचतान कर रहे हैं. पार्टी उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने इस सप्ताह के प्रारंभ में प्रादेशिक नेताओं की बैठक की, लेकिन आंतरिक मसलों को हल करने की कोई कोशिश नहीं की. कांग्रेस पार्टी बिहार के चुनाव में थोड़ी इज्जत वापस लाना चाहती है. लेकिन पिछले दस वर्षों में वह एक ऐसा दमदार नेता नहीं खड़ा कर पाई, जो पाटलिपुत्र में सेनापति की पहचान बना सके. उत्तर प्रदेश के लिए 'रणनीति' पर बैठकें होती हैं, लेकिन सपा, बसपा, भाजपा से टक्कर लेने के लिए पार्टी ने क्या कोई बहादुर तलवारबाज सामने रखा है? मध्य प्रदेश में 'व्यापमं घोटाले' को लेकर भाजपा सरकार गंभीर मुसीबत में आ गई. लेकिन दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दिल्ली से तीर चलाते रहे. ज्योतिरादित्य सिंधिया राज परंपरा के अनुरूप टी.वी.पर चमक-दमक के साथ 'स्टार राजनीति' कर रहे हैं. फिर म.प्र.में असली लड़ाई कौन लड़ सकता है.

भाजपा ने दिल्ली में मदनलाल खुराना और साहिब सिंह के बाद किसी नेता को उभरने नहीं दिया. हर्षवर्धन ने अपनी पहचान बनाई थी लेकिन पिछले चुनाव में 'चक्रवर्ती' नेतृत्व ने हर्षवर्धन को अपमानित करने के साथ नई नवेली किरण कार्यकर्ताओं के सिर पर बैठा दी. नतीजा यह हुआ कि तीस के बजाय तीन सीटें ही हाथ लग सकीं. बिहार में आठ साल सत्ता में भागीदारी के बावजूद भाजपा यह कहने की स्थिति नहीं बना पाई कि आगामी चुनाव के बाद मुख्यमंत्री का दावेदार कौन हो सकता है. लगभग यही स्थिति पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड जैसे प्रदेशों की है. विडंबना देखिए कि पर्वतीय राज्य उत्तराखंड से लोकसभा की पांचों सीटों पर भाजपा की विजय हुई, जिनमें तीन पूर्व मुख्यमंत्री हैं. लेकिन केंद्र सरकार में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व ही नहीं है. मतलब साफ है, किसी प्रदेश में बहुत मजबूत नेतृत्व नहीं बनना चाहिए. शायद इसीलिए वसुंधरा राजे, शिवराज सिंह पर हमलों से भाजपा नेतृत्व अंदर से प्रसन्न है! सबको दिल्ली का सिंहासन सुरक्षित रखने की इच्छा है. ■■

मंथन का अवसर है विश्व हिंदी सम्मेलन

कृपाशंकर चौबे
वरिष्ठ स्तंभकार

मध्य प्रदेश के भोपाल में 10 से 12 सितंबर 2015 तक होने जा रहे दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन ने इस पर मंथन का अवसर उपलब्ध कराया है कि जिन उद्देश्यों से इसके आयोजन की परंपरा चार दशक पहले प्रारंभ हुई थी, उसमें कितनी लक्ष्यपूर्ति हुई. विश्व हिंदी सम्मेलनों की अब तक के कार्यों की आलोचनात्मक समीक्षा श्रेयस्कर होगी. समीक्षा का यह उचित समय है.

विश्व हिंदी सम्मेलनों के आयोजन के चार दशक पूरे हो गए हैं. पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा की पहल पर आयोजित हुआ था जिसमें महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में स्थापित करने तथा विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्यालय मॉरीशस में खोलने का प्रस्ताव पारित किया गया था और बाद में दोनों प्रस्ताव फलीभूत भी हुए. दूसरी बार दिल्ली में 28-30 अक्तूबर 1983 तक विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था. भारत में यह तीसरी बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो रहा है. दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन को भारत में आयोजित करने का निर्णय सितंबर 2012 में दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित नौवें विश्व हिंदी सम्मेलन में लिया गया था. अब तक नौ विश्व हिंदी सम्मेलन विश्व के विभिन्न शहरों में आयोजित किए जा चुके हैं- दो बार पोर्ट लुई (मॉरीशस) में, दो बार भारत में, एक बार पोर्ट ऑफ स्पेन (ट्रिनिडाड एंड टोबेगो), एक बार लंदन (यूके) में, एक बार पारामारिबो (सूरीनाम) में, एक बार न्यूयॉर्क (अमेरिका) में और एक बार जोहान्सबर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में. इन सम्मेलनों ने अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप प्राप्त कर लिया है.

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन का मुख्य विषय 'हिंदी जगत : विस्तार एवं संभावनाएं' है. सम्मेलन में समकालीन मुद्दों और विषयों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रशासन और विदेश नीति, विधि, मीडिया आदि के क्षेत्रों में हिंदी के सामान्य प्रयोग और विस्तार से संबंधित तौर-तरीकों पर चर्चा होगी. निर्धारित विषयों के समानांतर शैक्षिक सत्र भी चलेंगे. ये सत्र हिंदी समाज और इसकी रचनाशीलता और हिंदी रचनाशीलता के विभिन्न स्वरूपों को समझने में सहायक होंगे, यह उम्मीद लाजिमी है. उम्मीद की जाती है कि इस सम्मेलन में भाषा-विज्ञानी गणेश एन. देवी के दल द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर किए गए भाषाओं के सर्वेक्षण के नतीजों पर भी विचार किया जाएगा. गणेश देवी का भाषा सर्वेक्षण आंखें खोल देनेवाला है. आजादी के बाद यह पहला भाषा सर्वेक्षण है. इसके करीब अस्सी साल पहले ब्रिटिश शासनकाल में आइरिश भाषा-विज्ञानी और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे जार्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने भाषा सर्वेक्षण

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन से यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के सहकारी संबंध को मजबूती देने के लिए अब तक हुए कार्यों की समीक्षा करेगा.

किया था. गणेश देवी के दल के भारतीय भाषाओं के लोक सर्वेक्षण में पाया कि भारत में करीब 850 भाषाएं हैं, जिनमें से यह दल 780 भाषाओं का ही अध्ययन कर सका. गणेश देवी के दल ने 1961 की जनगणना को आधार मानते हुए निष्कर्ष निकाला है कि पिछले 50 साल में करीब 250 भाषाएं लुप्त हुईं. इसके बावजूद भारत भाषा की दृष्टि से यूरोप के मुकाबले करीब चार गुना संपन्न है. भारतीय जहां करीब 850 भाषाएं बोलते हैं, वहीं यूरोपीय अपनी बात मात्र 250 भाषाओं में रख पाते हैं.

दसवें विश्व हिंदी सम्मेलन से यह अपेक्षा की जाती है कि भारतीय भाषाओं के साथ हिंदी के सहकारी संबंध को मजबूती देने के लिए अब तक किए गए कार्यों की वह समीक्षा करेगा. सम्मेलन में इस पर भी विचार किया जाना चाहिए कि हिंदी समाज में अपनी भाषा, साहित्य-कला-संस्कृति से सच्चे मन से प्रेम करनेवाले क्यों कम होते जा रहे हैं. भाषा-साहित्य-कला-संस्कृति हिंदी प्रदेशों के शिक्षित समाज के संस्कार का हिस्सा क्यों नहीं बन पाई है. सम्मेलन को दरअसल मातृभाषा और राष्ट्रभाषा को समाज में पुनर्प्रतिष्ठित करने के लिए नया एजेंडा भी तैयार करना चाहिए. ■■

बदला-बदला सा है प.बंगाल का मूड!

कृष्ण प्रताप सिंह
वरिष्ठ पत्रकार

बिहार की ही तरह 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के चुनाव भी अब ज्यादा दूर नहीं हैं और प्रतिद्वंद्वी दल वहां भी चुनावी बिसातें बिछाने लगे हैं. इससे जो हालात बन रहे हैं, उनसे लगता है कि प्रायः सारे प्रदेश में दिलचस्प चुनावी टक्कर देखने को मिलेगी.

प. बंगाल में तृणमूल कांग्रेस अपने साढ़े चार साल के शासन में मतदाताओं को परिवर्तन का अहसास नहीं करा पाई है.

सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने 2011 का पिछला चुनाव वाममोर्चे के चौंतीस साल के कथित कुशासन व गुंडागर्दी को मुद्दा बनाकर परिवर्तन के नाम पर लड़ा था और 227 सीटें जीतकर वाममोर्चे को 62 सीटों पर सिमटा दिया था. लेकिन बदली हुई परिस्थितियों में वह अपने साढ़े चार साल के शासन में मतदाताओं को उक्त परिवर्तन का अहसास नहीं करा पाई है. उसकी इस विफलता को वाममोर्चा, कांग्रेस व भाजपा अलग-अलग तरह से भुनाने के फेर में हैं. वाममोर्चे का प्रयास है कि मतदाता अपनी भूलसुधार कर फिर से उसे चुन लें, जबकि भाजपा व कांग्रेस उन्हें समझा रही हैं कि वे 'नया विकल्प' आजमाएं. तिस पर लगातार खराब होती कानूनव्यवस्था, महिलाओं के विरुद्ध अपराधों तक में राज्य सरकार के असंवेदनशील बर्ताव, मुख्यमंत्री की गैरजिम्मेदाराना टिप्पणियों और सारदा घोटाले में उनके सहयोगियों की लिप्तता के ठप्पे ने तृणमूल कांग्रेस के पास कहने के लिए ज्यादा कुछ बचने नहीं दिया है.

यही कारण है कि ममता लोक लुभावन घोषणाओं की शरण में चली गई हैं. पिछले दिनों उन्होंने घोषणा की कि फिर सत्ता में आईं तो जंगलमहल के उन 320 करोड़ लोगों के अलावा, जिनको दो रुपए किलो चावल उपलब्ध कराया जा रहा है, तीन करोड़ और लोगों को तीन रुपए किलो चावल उपलब्ध कराएंगी. यह घोषणा उनकी झोली वोटों से भरे या नहीं, चर्चा का विषय बन गई है. दूसरी ओर वाममोर्चे की सबसे बड़ी पार्टी माकपा की कमान सीताराम येचुरी के हाथ आने के बाद कई लोगों को उम्मीद थी कि वे उसकी रीति-नीति में व्यापक बदलाव लाएंगे. लेकिन न ऐसा होना संभव था और न हुआ. वामपंथी दलों में व्यक्ति नहीं, विचारधारा महत्वपूर्ण होती है और उसके महासचिव की स्थिति बुर्जुआ पार्टियों के स्वयंभू सुप्रीमो जैसी नहीं होती. उसे पार्टी की सर्वोच्च नीतिनिर्धारक संस्थाओं-पोलित ब्यूरो और सेंट्रल कमेटी-से बंधकर चलना होता है.

लेकिन ऐसा भी नहीं कि येचुरी ने कुछ नया किया ही न हो. निराश माकपा कार्यकर्ताओं में नया उत्साह भरने के उनके प्रयासों के चलते राज्य में माकपा के प्रदर्शनों व आंदोलनों को फिर से सफलता नसीब होने लगी है. ■■

नजर के पार

नए देश से हल होगी शरणार्थी समस्या?

शाहिद ए. चौधरी
वरिष्ठ पत्रकार

सीरिया के तीन साल के एक बच्चे की लाश को समुद्र तट पर भूखे गिद्धों के साए में देखने के बाद दुनिया भर के लोगों को अपने दिल डूबने व दिमाग के सुन्न होने का अहसास हुआ. लेकिन इस घटना से पहले भी जो लोग संसार भर में बढ़ते शरणार्थियों के संकट के प्रति संवेदनशील थे उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए आउट ऑफ द बॉक्स यानी लीक से हटकर सुझाव रखे हैं, जिनकी समीक्षा आवश्यक मालूम होती है. मसलन, कैलिफोर्निया यहूदी-अमेरिकी रियल एस्टेट डेवलपर जैसन बूजी ने कहा है कि शरणार्थियों के लिए एक अलग व विशिष्ट देश की स्थापना की जाए जिसमें न सिर्फ सीरिया व मध्य-पूर्व के संकटग्रस्त क्षेत्रों के शरणार्थी शरण लें बल्कि म्यांमार, लैटिन देशों के शरणार्थी भी पनाह ले सकें. इस नए देश को दुनिया के रईस लोग व सरकारें आर्थिक मदद कर सकती हैं. दूसरी ओर मिस्र के अरबपति नगीत सवारिस ने कहा है कि वह इटली व यूनान के पास से एक द्वीप खरीदने के लिए तैयार हैं ताकि उसमें शरणार्थी शरण ले सकें.

इसमें कोई दो राय नहीं है कि संकट समाधान का यह सुझाव परंपरागत सोच से अलग हटकर है और काफी हद तक इसे संभव भी किया जा सकता है क्योंकि संसार की बढ़ती जनसंख्या के बावजूद आज भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगहें हैं जैसे मध्य अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा व अनेक द्वीप जहां जनसंख्या कम है या बिलकुल नहीं है. इन क्षेत्रों को आबाद किया जा सकता है. लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सुझाव/प्रस्ताव व्यावहारिक भी है? संसार में हर क्षेत्र की अपनी संस्कृति, खानपान व रहने और जीवन

व्यतीत करने के अलग-अलग तरीके हैं. भाषाएं भी अलग-अलग हैं. ऐसे में अगर अलग-अलग पृष्ठभूमियों के शरणार्थियों को एक जगह बसा दिया जाएगा तो न केवल उनके लिए जीवन कष्टदायक होगा बल्कि उनमें आपस में भी संसाधनों व सत्ता अधिकारों के लिए टकराव हो सकता है. जैसन बूजी का कहना है कि यह व्यवस्था अस्थाई होगी फिर बाद में शरणार्थियों को अपने अपने देशों में लौटने का अवसर मिल सकेगा. लेकिन हम सभी जानते हैं कि यह बात ऐसे मामलों में कभी होती नहीं है. इसके बावजूद बूजी का कहना है कि शरणार्थियों के लिए शरणार्थियों द्वारा एक नए देश का विकास किए जाने का विचार कितना ही बेतुका प्रतीत हो, लेकिन आज इसे अमल में लाने की आवश्यकता है, सिर्फ राजनीतिक इच्छा की जरूरत है.

संभवतः बूजी से प्रेरित होकर मिस्र के अरबपति नगीद सवारिस ने कहा है कि वह यूनानी या इतालवी द्वीप खरीदने को तैयार हैं जहां शरणार्थी अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकते हैं. सवारिस लगभग तीन बिलियन डॉलर के मालिक हैं. रवींद्रनाथ टैगोर की पंक्ति का हवाला देते हुए सवारिस का कहना है कि आप समुद्र को ताकते रहने से समुद्र को पार नहीं कर सकते. द्वीप खरीदने का विचार पागलपन सा प्रतीत होता है लेकिन यह समस्या का समाधान है भले ही अस्थाई हो.

इस नए विचार के पक्ष व विपक्ष में कितने ही तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि जब पुराने तरीके काम न आ रहे हों तो एक नए विचार से प्रयोग करें, भले ही असफल हो जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है. ■■

तोल बोल

इतिहास को नए सिरे से लिखने का प्रयास किया जा रहा है. विशेष तौर पर नेहरू को निशाना बनाकर जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं.

■ **सोनिया गांधी**, कांग्रेस अध्यक्ष

मुजफ्फरपुर और गया की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद मैं ही अकेला नेता हूं जिसकी जनता ने सबसे ज्यादा तारीफ की.

■ **जीतनराम मांझी**, पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

gñWmnH$ gnmXH$: n{d. Odmhabmb XS>m
M`a_Z, E{S>Qmo[a`b ~moS>© : {dO` XS>m
E{S>Qa-BZ-Mr\$: amOB© XS>m
gnmXH$: {dH$mg {_l★
★ nr. Am. ~r. H$ZZ H$ AZgma gnU gnmXH$` Xm{` Ed H$ {bE {Oå_Xma.

© लोकमत समाचार _ àH$m{eV g^r gm_J«r H$m gdm©{YH$ma b{H$_V {S>`m àm`d{Q> {b. H$ nmg gm[j V h. b{H$_V _r{S>`m àm`d{Q> {b. H$ {bE _ÐH$ Ed àHmeH बालाजी मुले Ûmam b{H$_V _r{S>`m àm`. {b., ßb{Q> H$. 192, 207, 208 E_. AmB. S>r. gr. BÊS>{ñQ´>`b E[a`m, ~Wr~mar, ZmJnwa _{ÐV Ed b{H$_V ^dZ n. Odmhabmb Zhê _mJ, ZmJnwa _ àH$m{eV.
P.O.BOX NO. 230 R.N.I. No. 47101/89
XaÜd{Z : 0712-2423527 (7 bmB©Z) \¡S>g : 6618555
Email : gnmXH$s` : lsedit.ngp@lokmat.com
{dkmnZ : advt.ngp@lokmat.com {dVaU : circ.ngp@lokmat.com

इतिहास पर नजर 9 सितंबर

आज ही के दिन 1976 में आधुनिक चीन के संस्थापक माने जाने वाले माओ त्से तुंग की 82 साल की उम्र में मौत हो गई थी. आधी रात को हुए उनके देहांत की घोषणा सेंट्रल कमेटी ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने की. चेयरमैन माओ का स्वास्थ्य काफी समय से ठीक नहीं था और उन्होंने काफी समय तक कोई बाहरी यात्रा भी नहीं की थी. चीन की राजधानी में माओ की मौत की खबर आग की तरह फैल गई. कई लोगों ने शोक जताने के लिए हाथों में काले पट्टे बांधे. 1930 में माओ ने रेड आर्मी का गठन किया था. राष्ट्रवादियों पर 1949 में जीत हासिल करने के बाद माओ ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के गठन का ऐलान किया और उसके प्रथम नेता बने. चीन में लंबे खिंचे गृह युद्ध के दौरान उन्होंने सैन्य रणनीति में अपनी महारत दिखाई और चिंतक के रूप में अपना लोहा मनवाया. माओ ने 1949 से 1976 में अपनी मृत्यु तक चीन की सत्ता संभाली थी. ■■

- 1776-अमेरिकी संसद ने आधिकारिक तौर पर देश का नाम यूनाइटेड कालोनीज से बदलकर संयुक्त राज्य अमेरिका किया.
- 1828-महान रूसी उपन्यासकार लियो टॉल्सटॉय का जन्म.
- 1850-महान हिंदी साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म.
- 1867-लक्जमबर्ग आजाद हुआ.
- 1965-तिब्बत चीन का स्वायत्त क्षेत्र बना.
- 1967-युगांडा ब्रिटेन से आजाद हुआ.

पाठकों के पत्र

वतन के रखवालों की पूरी हुई मांग

पूर्व सैनिकों की वन-रैंक वन-पेंशन की मांग पर सरकार तकनीकी अड़चन का बहाना बनाती रही थी. खुशी की बात है कि अब उनकी मांग मान ली गई है. हालांकि कुछ छोटे-मोटे मुद्दे लंबित हैं, किंतु आशा है कि वे भी सुलझ जाएंगे. एक तरफ सरकार 1965 के युद्ध में पाकिस्तान पर विजय पाने की खुशी में इंडिया गेट पर गोल्डन जुबली का जश्न मना रही है और अफसोस की बात थी कि मात्र कुछ दूरी पर जंतरमंतर में सरहद पर जान हथेली पर लेकर लड़ने वाले सिपाही अपने जायज हक के लिए सड़क पर बैठे हुए थे. अब मांगें पूरी होने के बाद वे भी जश्न में शामिल हो सकेंगे.

■ संजय कुमार आर्य, नागपुर

क्रिकेट टीम की सफलता

भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका टीम को तीन मैचों की टेस्ट सिरीज में 2-1 से हराकर दिखा दिया कि उसमें कितना दम-खम है. इससे आलोचकों के मुंह भी बंद हो गए हैं. भारतीय टीम बधाई की पात्र है.

■ रूपेश अनेजा, चंद्रपुर

आप भी अपने पत्र हमें lsedit.ngp@lokmat.com पर मेल कर सकते हैं या डाक पते पर भेज सकते हैं.

विश्वास का फल

हास्य

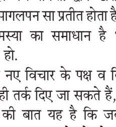

विश्वविद्यालय के उस विभाग के बारे में अक्सर यह सुनने में आता था कि वहां परीक्षाफल में भारी गड़बड़ होती है. आमतौर पर छात्र वहां प्रवेश लेने से बचते थे. फिर भी एक छात्र ने वहां प्रवेश लिया और परीक्षा में बैठा.

दूर-दराज के इलाके में रहने वाले उस छात्र के पास वहां प्रवेश लेने के पीछे कई कारण थे. एक तो उसे विभाग के ऊपर भरोसा था, दूसरे उसके पास कहीं और जाकर पढ़ने की सुविधा भी नहीं थी और तीसरी बात यह कि उसे अफवाहों पर विश्वास करना पसंद नहीं था.

जल्दी ही उसे अपनी इस नेक नीयती और निष्ठा का फल भी मिल गया.

बीमारी के कारण वह अंतिम पेपर नहीं दे पाया था, लेकिन फिर भी वह पास हो गया. उसने पत्र लिख कर पूछा कि ऐसा कैसे हुआ?

वहां से छपा-छपाया जवाब आया, 'यह बोर्ड का अंतिम निर्णय है.' ■■